



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012020-215672  
CG-DL-E-25012020-215672

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]  
No. 47]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2020/माघ 4, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2020/MAGHA 4, 1941

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

सं. 01/2020(एडीडी) सीमा-शुल्क

**सा.का.नि. 50(अ).**—जहां कि नामित प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन् पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “सोडियम नाइट्राइट” (एतश्मिन् पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2834 10 10 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 76/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 17 अगस्त, 2011, जिसे सा.का.नि. 628(अ), दिनांक 17 अगस्त, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन् पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण (नियमावली), 1995 (एतश्मिन् पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में और अधिसूचना संख्या 15/06/2016-डीजीएडी, दिनांक 27 जुलाई, 2016, जिसे दिनांक 27 जुलाई, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था के तहत तृतीय सनसैट रिव्यू जांच का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 76/2011-सीमा शुल्क, सा.का.नि. 628(अ), दिनांक 17 अगस्त, 2011 का अधिक्रमण करते हुए अधिसूचना संख्या 46/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 दिसम्बर, 2014, जिसे सा.का.नि. 877(अ), दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को जारी करके संशोधित दरों पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखा है;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या अधिसूचना संख्या 39/2016- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016, जिसे सा.का.नि. 773(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा 16 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दिया था (जिसमें यह तारीख भी शामिल है)।

और जहां कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में नामित प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 15/06/2016-डीजीएडी, दिनांक 19 जुलाई, 2017, जिसे दिनांक 19 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

- (i) विषयगत देश से संबंधित उत्पाद का यहां लगातार पाटन हो रहा है जिसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;
- (ii) इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग को कम बिक्री और कम कीमत का भी सामना करना पड़ रहा है;
- (iii) यदि इस प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इसके पाटन के जारी रहने की संभावना है और घरेलू उद्योग को क्षति होती रहेगी;

और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी;

और जहां कि नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1066(अ), दिनांक 25 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के तहत उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि घरेलू उद्योग ने माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), की प्रधान पीठ, नई दिल्ली में अपील करके दिनांक 19 जुलाई, 2017 के उक्त अंतिम निष्कर्षों को और उक्त सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 40/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 अगस्त, 2017 को चुनौती दी थी;

और जहां कि माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने अपने आदेश संख्या AD/A/50774/2019-CU (DB), दिनांक 17.06.2019 (Anti-Dumping Appeal No. 50401 of 2018) में अन्य बातों के अलावा यह निर्णय दिया है कि -

*एनआईपी के निर्धारण के बारे में दिनांक 19 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित उक्त नामित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं है अतः इसे निरस्त किया जाता है। इस प्रकार वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की गई दिनांक 25 अगस्त, 2017 की अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सही नहीं है। अतः इस मामले को उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास वापस इसलिए भेजा जा रहा है कि वे इस आदेश में दिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए एनआईपी का पुनःनिर्धारण करें। तथापि, दिनांक 25 अगस्त, 2017 की अधिसूचना के तहत लगाया गया शुल्क तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस बारे में वित्त मंत्रालय कोई नई अधिसूचना नहीं जारी कर देता है। तदनुसार उक्त स्थिति तक इस अपील को स्वीकार किया जाता है।*

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उठाए गए मुद्दों तथा संबंधित पक्षकारों के द्वारा दी गई सूचना और उनके कथनों और अपने पास उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अधिसूचना संख्या 15/06/2016-डीजीटीआर, दिनांक 8 नवम्बर, 2019, जिसे 8 नवम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत यह सिफारिश की है कि इस संशोधित प्रतिपाटन शुल्क को उस तारीख तक जारी रखा जाएगा जिस तारीख तक केन्द्र सरकार चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट, जो कि सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत आता है, के आयात के बारे में इस निमित्त कोई अधिसूचना नहीं जारी कर देती है। शुल्क सारणी के कॉलम 8 में उल्लेखित संशोधित राशि को ही प्रतिपाटन शुल्क माना जायेगा। यह प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना सं. 40/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 25.08.2017 के जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित, केन्द्र सरकार नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या

40/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 25 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1066 (अ), दिनांक 25 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

दी गई सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

**“सारणी**

क्र.सं.	उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	माप इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2834 10 10	सोडियम नाइट्राइट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	79.58	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	79.58	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	79.58	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर”.

[फा. सं. 354/41/2000-टीआरयू (भाग-VI)]

गौरव सिंह, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2020

**No. 01/2020-Customs (ADD)**

**G.S.R. 50(E).**—Whereas, the designated authority vide notification No. 15/06/2016 DGAD dated the 27<sup>th</sup> July, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27<sup>th</sup> July, 2016, had initiated third sunset review investigation in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Sodium Nitrite (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2834 10 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.76/2011-Customs, dated the 17<sup>th</sup> August 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 628(E), dated the 17<sup>th</sup> August 2011;

And whereas, the Central Government had issued the notification in supersession of notification No.76/2011-Customs, G.S.R.628 (E), dated the 17<sup>th</sup> August 2011 for continued imposition of

anti-dumping duty at the modified rates *vide* notification No. 46/2014-Customs (ADD), dated the 8<sup>th</sup> December, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.877 (E), dated the 8<sup>th</sup> December, 2014;

And whereas, the Central Government had extended the period of imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country up to and inclusive of the 16<sup>th</sup> August, 2017 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 39/2016-Customs (ADD), dated 8th August, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.773 (E), dated the 8th August, 2016;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the Designated Authority in its final findings, published *vide* notification No. 15/06/2016-DGAD, dated the 19<sup>th</sup> July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19<sup>th</sup> July, 2017 had come to the conclusion that—

- (i) there is continued dumping of the product concerned from subject country, causing injury to the domestic industry;
- (ii) imports are significantly undercutting and underselling the prices of the domestic industry;
- (iii) cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation and recurrence of dumping and injury to the domestic industry,

and had recommended continued imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed the anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 40/2017-Customs (ADD), dated the 25<sup>th</sup> August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1066(E), dated the 25th August, 2017;

And whereas the domestic industry filed an appeal before the Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Principal Bench, New Delhi challenging the Final Findings dated the 19th July, 2017 and the aforesaid Customs notification No 40/2017-Customs (ADD) dated the 25th August 2017;

And whereas the Hon'ble CESTAT *vide* final order No. AD/A/50774/2019-CU (DB), dated 17.06.2019 (Anti-Dumping Appeal No. 50401 of 2018) inter-alia decided as under: -

*"The final findings of the designated authority notified in the Government Gazette dated 19 July 2017 in regard to the determination of NIP, therefore, cannot be sustained and are set aside. Thus, the extent of imposition of duty in the notification dated 25 August 2017 issued by the Ministry of Finance is not correct. The matter is, therefore, remitted to the designated authority to re-determine the NIP, keeping in mind the observations made in this Order. However, the imposition of duty contained in the notification dated 25 August 2017 shall continue till a fresh notification is issued in this regard by the Ministry of Finance. The Appeal is, accordingly, allowed to the extent indicated above".*

And whereas, the designated authority after considering the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and the facts available before it, *vide* notification No. 15/06/2016-DGTR, dated the 8<sup>th</sup> November, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 8th November, 2019 has recommended that revised anti-dumping duties be continued to be imposed from the date of issue of notification by the Central Government on imports of Sodium Nitrite falling under chapter 28 of Custom Tariff Classification Act 1975, originating in or exported from China PR. The anti-dumping duty shall be the revised amount mentioned in Column No. 8 of the duty table. This anti-dumping duty will remain effective for 5 years from the date of Customs Notification No. 40/2017-Custom (ADD) dated 25.08.2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the final findings of the designated authority, hereby makes the

following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 40/2017-Customs (ADD), dated the 25th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1066(E), dated the 25th August, 2017, namely:-

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely: -

**“TABLE**

Sl. No.	Sub- heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Produce r	Exporter	Duty Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2834 10 10	Sodium Nitrite	China PR	China PR	Any	Any	79.58	MT	US\$
2	-Do-	-Do-	China PR	Any Country other than China PR	Any	Any	79.58	MT	US\$
3	-Do-	-Do-	Any Country other than China PR	China PR	Any	Any	79.58	MT	US\$”.

[F. No. 354/41/2000-TRU (Pt.VI)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.